

**L. A. BILL No. XXXVI OF 2023.**

**A BILL**

**FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SLUM AREAS  
(IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971.**

**विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३६ सन् २०२३।**

**महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में  
अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।**

सन् १९७१ का महा. २८। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में अधिकतर संशोधन करना और भूतलक्षी प्रभाव से शीर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोष समितियों से संबंधित तद्दीन जारी सरकारी नियमों और अधिसूचना को पुनःअधिनियमित करना और अतः उसके उपबंधों को विधिमान्य करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरावें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :-

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (संशोधन, शीर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोष समितियों के नियमों और अधिसूचना का पुनःअधिनियमितकरण तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

(शा.म.मु.) एचबी ११५७-१ (५५-७-२०२३)

सन् १९७१ का  
महा. २८ की धारा  
२ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा २ के,—

(एक) खण्ड (क) के पश्चात् निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा और ८ मार्च २०१७ से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

“(क-१) “शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति” का तात्पर्य, धारा ३४क की, उप-धारा (१) के अधीन गठित शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति, से है;” ;

(दो) खण्ड (ग-ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

“(ग-ग) “शिकायत प्रतितोष समिति” का तात्पर्य, धारा ३४ख की, उप-धारा (२) के अधीन गठित शिकायत प्रतितोष समिति से है;” ।

सन् १९७१ का  
महा. २८ की धारा  
३ग में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ग की, उप-धारा (२) में, “शिकायत प्रतितोष समिति” शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आए हों, के स्थान में “शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति” शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च, २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे।

सन् १९७१ का  
महा. २८ की धारा  
३घ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३घ के, खण्ड (ख) के,—

(एक) उप-खण्ड (दो) (ग) की, उप-धारा (४) में, “शिकायत प्रतितोष समिति” शब्द दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, “शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति” शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (दो) (घ) की, उप-धारा (५) में, “शिकायत प्रतितोष समिति” शब्द, जहाँ कहीं वे आए हों, के स्थान में, “शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति” शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(तीन) उप-खण्ड (दो) (ज) की उप-धारा (१०) के, परंतुक में, “शिकायत प्रतितोष समिति” शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आए हों, के स्थान में, “शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति” शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(चार) उप-खण्ड (तीन) की, धारा १३ की, उप-धारा (३) के, तृतीय परंतुक में, “शिकायत प्रतितोष समिति” शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आए हों, के स्थान में, “शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति” शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ।” ।

सन् १९७१ का महा.  
२८ में नई धारायें  
३४क और ३४ ख  
का निवेशन।

५. मूल अधिनियम की धारा ३४ के पश्चात्,—

(१) निम्न धारा निविष्ट की जायेगी और ८ मार्च २०१७ से निविष्ट की गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

“३४क. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन जैसा कि उसे समनुदेशित किया जा सके, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष और सरकार जिसे उचित समझे ऐसी संख्या के सदस्यों से मिलकर शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति का **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा गठन करेगा।

(२) शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति की, शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा कृत्यों का अनुपालन करेगी अर्थात् :—

(एक) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अधिकारी जिसको, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है, के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना तथा निपटान करना ;

(दो) राज्य सरकार उसके द्वारा निर्देशित कोई प्रश्न या मामले ;

(३) शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, उनके कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया तथा उनकी बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए । ” ।

(२) इसप्रकार निविष्ट की गई धारा ३४क के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, और ८ मार्च २०१७ से निविष्ट की गई समझी जायेगी, अर्थात् :-

“ ३४ख (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जैसा कि उसे समनुदेशित किया जा सके, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष और सरकार जिसे उचित समझे ऐसी संख्या के सदस्यों से मिलकर शिकायत प्रतितोष समितियों का राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठन करेगी।

शिकायत प्रतितोष समितियों का गठन।

(२) शिकायत प्रतितोष समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, उनके कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया तथा उनके बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए । ” ।

६. मूल अधिनियम की धारा ३५ की,—

(१) उप-धारा (१क) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :-

सन् १९७१ का  
महा. २८ की धारा  
३५ में संशोधन।

“(१क) कोई व्यक्ति,—

(क) उप-धारा (१) के अधीन अपील प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए या दिए गए किसी सूचना, आदेश या निदेशन से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे सूचना, आदेश या निदेशन की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर शिकायत प्रतितोष समिति के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा ;

(ख) मलिन बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अधिकारी जिसको मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, द्वारा जारी या दिए गए किसी सूचना, निदेशन, परिपत्रक, विनिर्णय, आदेश, अनुमति या अनुमोदन से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश, सूचना, निदेशन अनुमति या अनुमोदन की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा।

२. उप-धारा (५) में, “ शिकायत प्रतितोष समिति ” शब्दों के स्थान में, “ शिकायत प्रतितोष समिति और शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति ” शब्द रखे जायेंगे ।

७. मूल अधिनियम को धारा ४२ में, “ शिकायत प्रतितोष समिति ” शब्दों के स्थान में, “ शिकायत प्रतितोष समिति और शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति ” शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९७१ का  
महा. २८ की धारा  
४२ में संशोधन।

सन् १९७१  
का महा.  
२८ ।

८. महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में या किसी न्यायालय अधिकरण या प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समितियों से संबंधित महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) (शिकायत प्रतितोष समिति) नियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे, “ नियम ” कहा गया है) २३ फरवरी २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा पुनःअधिनियमित करना सम्यक् तथा विधिमान्य समझा जायेगा और सभी तात्त्विक समर्थों पर प्रचालन में रहे है ऐसा समझा जायेगा, मानों कि वे इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसरण में बनाए गए है।

महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार उन्मुलन और पुनर्विकास) (शिकायत प्रतितोष समिति) नियम, २०१४ का भूतलक्षी प्रभाव से पुनःअधिनियमितकरण।

शीर्ष या अन्य शिकायत प्रतितोष समितियों के गठन संबंधि दिनांकित ८ मार्च २०१७ की सरकारी अधिसूचना का पुनः अधिनियमितकरण।

९. महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति से संबंधित सरकारी अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग की क्र. झोपसु १००८/ प्र.क्र. १४३(१)/मलीन बस्ती-१ दिनांकित यह ८ मार्च २०१७ (जिसे इसमें आगे, “अधिसूचना” कहा गया है) ८ मार्च २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा पुनः अधिनियमितकरण सम्यक् तथा वैध रूप से बनाई है ऐसा समझा जायेगा और सभी तात्त्विक समयों प्रचालन में रहे हैं ऐसा समझा जायेगा, मानों कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

सन् १९७१ का महा. २८।

विधिक कार्यवाहियों का उपशमन।

१०. महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ या शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के संबंध में किये गये नियम या जारी अधिसूचना के अनुसरण में या शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति या शिकायत प्रतितोष समितियों द्वारा बनाया गया या जारी किए गए आदेशों, विनिर्णयों, सूचनाओं, परिपत्रकों, संकल्पों, निदेशनों या उसकी कोई अन्य कार्यवाहियों के संबंध में किसी न्यायालय अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष विलंबित सभी विधिक कार्यवाहियाँ, उस आधार पर शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समितियाँ किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रश्न या चुनौती होगी के गठन और उसकी शक्तियाँ तथा कृत्य उक्त अधिनियम, में उपबंधित नहीं किए गए थे और उक्त समिति को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा करने की अधिकारिता नहीं थी या ऐसा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं थी, के नियम और अधिसूचना का और ऐसे गठन से उद्भूत सभी प्रलंबित कार्यावाहियाँ का उसी विस्तार से उपशमन होगा।

सन् १९७१ का महा. २८।  
सन् २०२३ का महा. ....।

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

११. महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी या किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश के उल्लंघन में, ८ मार्च २०१७ से प्रारम्भ होनेवाली तथा महाराष्ट्र मलिन बस्ती (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) (संशोधन, शीर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोष समिति के नियमों और अधिसूचना का पुनः अधिनियमितकरण और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में, “संशोधन अधिनियम” कहा गया है) के प्रारम्भ के दिनांक पर समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान, शीर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समितियों द्वारा पारित आदेशों समेत कृत या किए गए सभी कृत्यों, कार्यवाहियों या बातों जो उक्त अधिनियम के अधीन नियमों और अधिसूचनाएँ की गई समझी जायेगी और हमेशा विधि के अनुसरण में सम्यक् रूप से तथा वैध रूप से की गई समझी जायेगी मानों कि संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर निरंतर प्रवर्तन में रहे थे और तदनुसार, उक्त समिति द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, किसी मलिन बस्ती पुनर्वास योजना के संबंध में किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा कृत या की गई सभी कार्यवाहियाँ या कार्य, सभी प्रयोजनों के लिए की गई समझी जायेगी और संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में हमेशा कृत या की गई समझी जायेगी।

सन् १९७१ का महा. २८।

सन् २०२३ का महा. ....।

कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति।

१२. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, मूल अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई ऐसी बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

### उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (सन् १९७१ का महा. २८) राज्य में मलिन बस्ती का सुधार तथा उन्मूलन करने के लिए और उनका पुनर्वास तथा बेदखल करने तथा करस्थम् अधिकारपत्र से अधिभोगियों का संरक्षण करने के लिए बेहतर उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम का अध्याय एक-क में, राज्य सरकार के पूर्व मंजूरी के साथ मलिन बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा संरक्षित अधिभोगियों को नए स्थान पर बसाने और पुनर्वास करने के लिए मलिन बस्ती पुनर्वास योजना की तैयारी के लिये कतिपय उपबंध अंतर्विष्ट है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ३५ **अन्य बातों के साथ** राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा गठित शिकायत प्रतितोष समिति के समक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, मलिन बस्ती पुनर्वास क्षेत्र, उन्मूलन आदेश, बेदखल आदेश आदि, की घोषणा के संबंध में मलिन बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण के विरुद्ध अपील दाखिल करने के लिए उपबंध करती है।

सरकारने, उक्त अधिनियम की धारा ३५ के अधीन अपीलों की, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समिति का गठन करने के लिए दिनांकित ८ मार्च २०१७ को एक अधिसूचना जारी की है। शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति समेत शिकायत प्रतितोष समिति के कारोबार के संव्यवहार करने की प्रक्रिया विहित करने के लिए महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (शिकायत प्रतितोष समिति) नियम, २०१४ तैयार की है। अधिसूचनाओं के लिये अधिकार स्रोत के किसी संदेह के निराकरण के उद्देश्य से और शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समितियों को अपीलों और अधिकारिता के लिये स्पष्ट उपबंध भी करना है। सरकार, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के गठन के लिए तथा उनकी शक्तियाँ तथा कृत्यों का भूतलक्षी प्रभाव से उपबंध करने तथा उसके लिए आवश्यक विधिमान्य उपबंध करने के लिए महाराष्ट्र मलिन बस्ती (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में यथोचित संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,  
दिनांकित २६ जुलाई, २०२३।

अतुल सावे,  
गृहनिर्माण मंत्री।



## प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्राह्य है, अर्थात् :—

**खंड ५.**—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय राज्य सरकार को, महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में नवीन धारा में ३४क और ३४ख निविष्ट करने की शक्ति यथा निम्न में प्रदान की गई है,—

(क) शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समिति का गठन **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा करना ; और

(ख) शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समिति के अध्यक्ष और ऐसी संख्या के सदस्यों की अर्हताएँ, उनके कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया, उनके बैठकों के लिए गणपूर्ति विहित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

**खंड १२.**—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, जो अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हो सके, कोई कठिनाई का निराकरण करने के लिए कोई आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

**विजया ल. डोनीकर,**  
भाषा संचालक,  
महाराष्ट्र राज्य।

**विधान भवन :**

मुंबई,

दिनांकित २६ जुलाई, २०२३ ।

**जितेंद्र भोळे,**

सचिव (१) (कार्यभार),

महाराष्ट्र विधानसभा।